आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 18.03.2026 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- स्वास्थ्य विभाग को 30 और विशेषज्ञ चिकित्सक मिले। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी दी। कहा– पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
- कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटन सीजन से पहले देहरादून–मसूरी मार्ग पर एक अतिरिक्त बेली ब्रिज निर्माण के अधिकारियों को निर्देश दिए।
- चम्पावत, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए व्यापक पूर्वाभ्यास किया गया।
- चमोली जिले के गोपेश्वर में तीन दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।

विशेषज्ञ चिकित्सक

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को 30 और विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार की मंशा प्रत्येक चिकित्सा इकाईयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कर आम लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करना है। इसी कड़ी में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राज्य सेवा में लौटे इन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नवीन तैनाती को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके विशेषज्ञता के अनुरूप विभिन्न जिलों में एक यूनिट के रूप में तैनाती दी गई है, ताकि विशेषज्ञ चिकित्सकों का आपसी समन्वय बना रहे और मरीजों को आसानी से उपचार मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निरंतर तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से न सिर्फ प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र सुदृढ़ होगा, बल्कि आम लोगों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से उचित उपचार मिलेगा। साथ ही चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होंगी।

गणेश जोशी

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए देहरादून–मसूरी मार्ग पर स्थित बेली ब्रिज के संबंध में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आज देहरादून में बैठक की। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने प्रस्तावित नए पुल के निर्माण से पूर्व अस्थायी बेली ब्रिज के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से पर्यटन सीजन प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे में देहरादून–मसूरी मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ेगा। इसलिए समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग और वन विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए शीघ्र ही एक अतिरिक्त अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करें, ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पूर्व चेतावनी प्रणाली

बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन–टीएचडीसी ने उत्तरकाशी और टिहरी जिले के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की हैं। इनके माध्यम से ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाली बारिश, बर्फबारी और नदी के जलप्रवाह का रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे आपदा की स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी करना संभव होगा। परियोजना के तहत भागीरथी और भिलंगना जलग्रहण क्षेत्र में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित

किए गए हैं। पहले चरण में 10 स्टेशन लगाए गए थे, जबकि दूसरे चरण में पांच नए स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा नदियों के जलप्रवाह की निगरानी के लिए स्वचालित गेज और डिस्चार्ज स्टेशन भी लगाए गए हैं। हर्षिल, धरासू, घनसाली और सरासगांव में ऐसे स्टेशन पहले से संचालित हैं, जबकि नए स्टेशन झाला, मनेरा बाईपास, टेखला ब्रिज, जालकुर गाड़, अनिल गाड़, बुढाकेदार क्षेत्र और धोपड़धार में स्थापित किए गए हैं। ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ की स्थिति का पता लगाने के लिए गंगोत्री और हर्षिल में स्नो गेज लगाए गए हैं। वहीं जलस्तर की निगरानी के लिए टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं। टीएचडीसी के अधिकारी अमित रावत ने बताया कि यह पूरी प्रणाली अंतर्प्रवाह पूर्वानुमान के तहत काम करेगी। इसके माध्यम से ऊपरी क्षेत्रों में होने वाली भारी बारिश या बादल फटने की स्थिति में टिहरी बांध में आने वाले पानी की मात्रा का पहले से अनुमान लगाया जा सकेगा, जिससे समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।

मॉक ड्रिल

चम्पावत, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में आज आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूस्खलन, बाढ़, भूकम्प, वनाग्नि और वन्यजीव हमले जैसी विभिन्न आपदा परिस्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और चिकित्सा विभाग सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट और बेरीनाग तहसील समेत जिला मुख्यालय में आपदा के अलग–अलग परिदृश्यों को लेकर अभ्यास किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का स्थलीय निरीक्षण किया और कंट्रोल रूम से जिलेभर में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

उधर, चम्पावत और चमोली जिलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने अपने दो दिवसीय नैनीताल प्रवास के दौरान डॉ. आर.एस टोलिया प्रशासनिक अकादमी में जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि लागत में वृद्धि न हो और जनसुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक, तकनीकी या प्रक्रियागत बाधाओं का त्वरित समाधान कर कार्यों को अवरुद्ध न होने दिया जाए तथा लंबित निविदाएं, स्वीकृतियां और तकनीकी अनुमोदन शीघ्र पूर्ण किए जाए। उन्होंने विभागों को मासिक लक्ष्य तय कर नियमित अनुश्रवण करने, गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आगामी ग्रीष्मकालीन पर्यटन सत्र को दृष्टिगत रखते हुए यातायात, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। उन्होंने एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति व गृह वितरण सुनिश्चित करने की बात भी कही। मुख्य सचिव ने नमो भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारणों और इस संबंध में बनाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि के संबंध में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के कुमाऊं आयुक्त को निर्देश दिए।

जनगणना प्रशिक्षण

चमोली के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में गोपेश्वर में आज से तीन दिवसीय जनगणना–2027 प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस दौरान 30 फील्ड प्रशिक्षेकों को जनगणना संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य फील्ड प्रशिक्षकों को जनगणना सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि जनगणना–2027 देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जो दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना व दूसरे चरण में जनगणना की जाएगी।

अवैध अतिक्रमण

हरिद्वार जिला प्रशासन और सिडकुल पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सका। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई, उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय के बावजूद उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया।